

सम्पादकीय...

आंदोलन का प्रभाव सीमित ही बना हुआ

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 20 महीनों तक संघर्षरत रहने के बाद एसकेएम को कामयाबी मिली। लेकिन इस तरीके को हर संघर्ष की सफलता का सूत्र मान लेना कितना उचित है, इस पर एसकेएम के अ-राजनीतिक गुट को अवश्य विचार करना चाहिए।

अपने को गैर राजनीतिक कहने वाले संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का संघर्ष लगातार गतिरोध का शिकार बना हुआ है, तो उसके पीछे खुद इस गुट की अपनी सोच कम जिम्मेदार नहीं है। एक तरीका एक मामले में सफल हुआ, तो उसे ही अच्युत या कहीं व्यापक मुद्दों पर अपनाने की समझ समस्याग्रस्त है। 2020 में तीन कृषि कानून पारित होने से किसानों के सामने एक फौरी चुनौती पेश आई थी, जिस पर प्रतिरोध जताने के लिए के बैठक दिल्ली आए। चूंकि दिल्ली में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया, तो तीन दिशाओं से आए किसान दिल्ली से लगी तीन सीमाओं पर बैठ गए। 20 महीनों इसी रूप संघर्षत रहने के बाद उन्हें कामयाबी मिली। इसे हर संघर्ष में सफलता का सूत्र मान लेना कितना उचित है, इस पर अ-राजनीतिक गुट को अवश्य विचार करना चाहिए।

इस गुट ने बाकी समूहों की तुलना में खुद को अधिक रैडिकल दिखाने के लिए एसकेएम की एकता तोड़ दी। जब एसकेएम ट्रेड यूनियनों और अन्य जन संगठनों के साथ मिल कर अपने आंदोलन को बड़ा संदर्भ देने की दिशा में बढ़ रहा था, तब इस समूह ने दलील दी कि किसानों को किसान मुद्दों तक ही सीमित रखना चाहिए। इस रूप में देश की राजनीतिक-अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरूप के प्रति इस समूह एक तरह का भोलापन दिखाया। अपनी मांगों को मनवाने के लिए उसने फिर दिल्ली कूच किया, जिसे हरियाणा के पहले ही शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। तब से वे ही बैठे रहे हैं।

अब छह दिसंबर से उन्होंने फिर से दिल्ली आने की मुहिम शुरू की है, जिसको लेकर दो दिन उनका पुलिस से टकराव हो चुका है। किसानों की मांगों में ऐमएसपी की कानूनी गारंटी, कृषि कर्ज माफी, बिजली की कीमतें ना बढ़ाना, किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन जैसी मांगें शामिल हैं। इसके अलावा वे 2021 के लखीमपुर खीरी हिस्सा के पीडिघ्टों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 को बहाल करने और 2020-21 के आंदोलन में मरे किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। फिर भी आंदोलन का प्रभाव सीमित ही बना हुआ है।

सत्ता और पद के नशे से लड़खड़ता सिस्टम

जब भी समाज घातक घटनाओं को नजरअंदाज करता है और उन पर कोई स्टैंड नहीं लेता तो वे नजीर बन जाती हैं। अठारह साल पहले स्व जुगलकिशोर बागरी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के एक बाबू का कालर पकड़ लिया था वे तब जल संसाधन मंत्री थे।उसी काल में एक और मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भी एक डाक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था।घटनायें तो भुला दीं गई किंतु विकृति बढ़ती गई है।देश आज जिस राह पर है वह निश्चित ही चौंकाने वाला है।प्रतिक्रियायें हिंसक और उन्नादी होती जा रही हैं।सीमायें अपने आप टूट रहीं हैं।ऐसा क्यों हो रहा है।पूर्व में हुई तीन घटनाओं की तरह एक ही सप्ताह में फिर से वैसी ही नई घटनायें सामने आ गई हैं।जो झकझोरती हैं।इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने अपने सार्वजनिक भाषण में अल्पसंख्यकों को कठमुल्ला कहते हुए उन्हें देश के लिये खतरनाक बताया है।वे कथित रूप से बहुसंख्यकों के अनुसार देश चलाने की बात भी कहते हैं।उनके विरुद्ध महाअभियांग लाने की बात हो रही है।यह रेडिकिलाईजेशन (कट्टरता) की नई नजीर है।इससे भी खतरनाक घटना गाजियाबाद के जिला जज द्वारा छोटी सी बात पर वकीलों से हुए वाद विवाद में जिला न्यायाधीश और वकीलों के बीच में कथित झूमा झटकी की है, जहां पुलिस द्वारा वकीलों की जबरदस्त पिटाई के बाद वकीलों द्वारा अदालत के बाहर पुलिस चौकी में आग लगा देने की है।यह दोनों घटनायें न्यायपालिका के आचरण पर रोशनी डालती हैं।अगर न्यायाधीश इतने ही प्रतिक्रियावादी हो जायेंगे तब निष्पक्ष न्याय की परिकल्पना ही व्यर्थ है।कल तक तो न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी थी लेकिन आज तो पट्टी हटा दी गई है, तब जजों और वकीलों का यह कथित व्यवहार स्पष्ट संकेत है कि प्रतिक्रिया का उत्तेजक जहर पूरे कुंए में घुल चुका है।एक राष्ट्रीय दल के बड़े नेता के विरुद्ध विदिशा में शर्मनाक मामले में एफआईआर दर्ज हुई है।उसकी भतीजी ने ही उस पर यौन शोषण और रेप के आरोप लगाये हैं।हालांकि भाजपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया है किंतु यह वासनागत उन्नाद की पराकाष्ठा है।

www.williammccormick.com | 800-222-1111 | 1-800-222-1111

आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ा संविधान पर चर्चा का सब्र

जहां विपक्ष ने आरक्षण विरोधी आरोपों को दोहराते हुए कहा कि सत्ता पक्ष मूल रूप से आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है और जब-तब दबे-छुपे ढंग से उसकी यह अंदरूनी इच्छा संघ और पार्टी के छोटे-बड़े नेताओं के बयानों से जाहिर होती रहती है। सर्वोच्च लोकतांत्रिक सदन लोकसभा संजीदा बहस की जगह हंगामे का केंद्र बनती जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण एवं विद्यमनापूर्ण है। जहां जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक बहस की जगह शोर शराबा, हंगामा और सदन का स्थगित होना ही आम होता जा रहा है। यही बात लोकसभा में संविधान को लेकर हुई दो दिनों की बहस की चर्चा के दौरान देखने को मिली। संविधान निर्माण के 75वें वर्ष पर ही यह चर्चा भी बहस में आरक्षण, सावरकर, मनुस्मृति और अदाणी को शामिल करना विपक्ष की बुद्धि का दिवालियापन ही कहा जा सकता है। इनमें से अनेक प्रसंग और विषय ऐसे थे, जिन पर पहले भी किसी न किसी बहाने संसद के भीतर या बाहर चर्चा होती रही है। यह पहले से दिख रहा था कि विपक्ष संविधान पर चर्चा के बहाने यह बताने की कोशिश करेगा कि संविधान खतरे में है। लेकिन यह समझाने के लिए विपक्षी नेताओं के पास कोई मजबूत तर्क नहीं थे, वे यह स्पष्ट करने में विफल रहे कि आखिर संविधान को खतरा कैसे है? कांग्रेस संविधान पर चर्चा करते समय यह भी भूल गई कि वह यदि मोदी सरकार के एक दशक के कार्यकाल की गलतियां शिनारेगी तो उसे भी अपने चार टंशकों कठघरे में खड़ा करने का काम ईर्षया और मात्सर्य की भावना से किया, जो तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास को ही बल दे रहा था। लगता है कि विपक्षी नेता यह समझने को तैयार नहीं किंतु लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने संविधान के खतरे में होने का जो हौवा खड़ा किया था, वह अब असरकारी नहीं रह गया है। विपक्ष के रवैये से यही लगा कि उसे यह बुनियादी बात समझने में मुश्किल हो रही है कि जाति जनगणना कराने—न कराने से संविधान की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? कांग्रेस के लिये यदि जाति जनगणना इतनी ही आवश्यक है तो नेहरू, इदिरा, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्यों नहीं कराई गई? अच्छा होता कि कांग्रेस नेता पहले इस पक्षन का

A wide-angle view of the Indian Parliament's Lok Sabha chamber during a session. The central podium is visible, and large screens at the top show the seating arrangement of the house.

इसका मतलब उनके हर विचार से सहमति रखना या उनके हर कृत्य को समर्थन देना नहीं है। लेकिन उनके प्रति समाज की या उसके एक हिस्से की भी भावनाओं का सम्मान हमारी राजनीति का हिस्सा होना चाहिए। सत्ता पक्ष ने इमरजेंसी का पुराना आरोप भी उछला, लेकिन नई बात यह रही कि इस पर बचाव की मुद्रा अपनाने के बजाय कांग्रेस इस तर्क के साथ सामने आई है कि भाजपा को भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन यहां इमरजेंसी जैसी कोई भाजपा की गलती बताने में कांग्रेस नाकाम ही रही। एक और बड़ी विडम्बना यह देखने को मिली कि संविधान निर्माण को किसी दल विशेष की देन कहा गया जबकि संविधान निर्माण में सभी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर विशेषतौर पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि पिछले कुछ वर्षों से देश में ऐसा माहौल बनाया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है, जबकि वास्तविकता यह है कि संविधान के निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका रही है जिसे पूरी तरह से नकार दिया गया। संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था, वह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि वह जनआकंक्षाओं का प्रतिबिंध था।

उन्होंने कहा कि संविधान पार्टी विशेष नहीं बल्कि राष्ट्र का है, पार्टी विशेष ने संविधान निर्माण को हार्ड्जैक कर लिया। निश्चित ही संविधान देश का सुरक्षा कवच है। लोकसभा में संविधान पर बहस की मूल आवश्यकता उन कारणों पर बुनियादी चर्चा की थी जिनके चलते संविधान निर्माताओं के सपने अभी भी अधूरे हैं और नियम—कानूनों पर संविधान की मूल भावना के अनुरूप पालन नहीं हो पा रहा है। बहरहाल, इसमें शक नहीं कि बहस का केंद्र यही सवाल रहा कि कौन संविधान और संवैधानिक मूल्यों को लेकर समर्पित है और कौन इस पर दोहरा खेल खेल रहा है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जहां सावरकर के सहारे भाजपा पर निशाना साधा वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की गलतियां गिनाईं।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने संविधान के रूप में मिले सुरक्षा कवच को तोड़ा है। भारत का संविधान, संघ का विधान नहीं है। इसी बात को दोहराते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। विपक्ष के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो देश एवं दुनिया भलीभांति देख रही है। मोदी के शासन में न केवल देश के भीतर शांति एवं अमनचौन बना है बल्कि सीमाओं पर भी सुरक्षा मजबूत हुई है। पड़ोसी देश भारत की ओर नजर करने का दुर्स्साहस नहीं कर पा रहे हैं तो इससे अधिक सीमा की सुरक्षा एवं देश की सुरक्षा क्या हो सकती है? उचित होता संविधान पर चर्चा के दौरान बहस के स्तर को ऊंचा उठाते हुए आरोप-प्रत्यारोप से बचते हुए संविधान को प्रभावी तरीके से लागू करने में सहायक बनने वाले बिंदुओं पर सहमति कायम की जाती।

विपक्षी एलायंस को जिंदा रखने राहुल को डिस्क्रेडिट करो

हरिशंकर व्यास

यदि राहुल गांधी राजनीति से रिटायर हो जाएं, विदेश जा कर बस जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी चौन की वह सांस लेंगे, जिसकी हम—आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मोदीजी के भारत को आज चाहिए राहुल व सोनिया गांधी की कुरबानी। इसलिए क्योंकि राहुल को मोदी, अडानी न खरीद सकते हैं और न बोलने से रोक सकते हैं। जबकि सोनिया गांधी इसलिए समस्या है क्योंकि वह पुत्रमोह में हैं और इसके चलते वे उनसे कांग्रेस की कमान नहीं लेती हैं तो जिद्दी राहुल को बोलने से रोक भी नहीं सकती। यहीं वह सत्व—तत्त्व है, जिस पर यह राजनीति है, प्रायोजित मीडिया से हल्ला है कि इंडिया' ब्लॉक की लीडरशीप के लायक कांग्रेस नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी इंडिया' ब्लॉक की नेता बने। नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर परस्पेशन डाउन है तो विषय के लायंस को बचाना है तो किसी दूसरी पार्टी का नेता इंडिया' ब्लॉक की लीडरशीप संभाले। जाहिर है राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करो, उसे हाशिए में रखो ताकि विपक्षी एलायंस जिंदा रह सके। इस तरह की राजनीति को मैं जनता पार्टी याकि मोरारजी देसाई, चरण सिंह, मधु लिमये, राजनारायण के समय से देखता आ रहा हूँ। धीरुभाई अंबानी के दिनों में वीपी सिंह, देवीलाल, शरद यादव के राज में थी। अंबानी के समय श्यांदी की जूतियाँ का जुमला था। लेकिन तब और अब का फर्क यह है कि इन दिनों से ठीं सरकार है और श्नोटों से भरे कटेनरों से चुनाव जैसे जुमले हैं। इतिहास की कथाओं, दंतकथाओं का यह सत्य है, जो दिल्ली में मुगल दरबार और अंग्रेजों से नेहरू के समय तक भारत के धनपति या जगत सेठ नजराना पेश कर सकते थे लेकिन वे शासन चलाने की ओकात नहीं रखते थे। अंग्रेजों ने लूटा लेकिन देशी सेठों के बष्टाचार पर मोहर नहीं लगाई। टाटा—बिडला, अपनी उद्यमशीलता में बने थे और इनकी कंपनियां अंग्रेज कंपनियों से कंपीट करते हुए थीं। बिडला में हिम्मत थी जो गांधी को अपने घर में ठहराते थे। उन्हें चंदा देते थे!

जाहिर है राहुल गांधी की वह निडरता व फकीरी है जो अपने हाल में राजनीति करते हुए है। भले पार्टी भूखे मरे या कड़की में रहे। इमानदारी से साँचे, पिछले दस वर्षों की राजनीति तथा मोदी-अडानी के वर्चस्व में विपक्षी नेताओं के व्यवहार का लब्बोलुआब निकालें तो क्या निकलेगा? क्या यह नहीं कि सरकार का विरोध तो राहुल गांधी से ही है। यदि मोदी ने सत्ता का पहाड़ अपनी ऊंगली पर उठाया हुआ है तो राहुल गांधी की ऊंगली पर विपक्ष का पहाड़ है। राहुल गांधी ही वह बला है, जिससे राफेल से अडानी तक का मसला घर-घर पहुंचा है। और यह इसी सप्ताह भाजपा के फ्रांसीसी मीडिया समूह श्मीडिया पार्ट के हवाले आरोप से मालूम हुआ कि यह वेबसाइट राफेल के पीछे अभी भी पड़ी हुई है। भाजपा ने इसके हवाले जो आरोप लगाए उन पर श्मीडिया पार्ट ने उलटे यह बयान दिया है कि भाजपा झूट बोल रही है। उसके दोष गलत हैं तथा अब यह एक स्थापित तथ्य है कि मोदी सरकार 36 राफेल लड़कू विमानों की खरीद संभी अट्टाचार के मामले को हर कीमत पर दफन करने की कोशिश कर रही है। फ्रांसीसी न्यायिक जांच में बाधक रही है। मतलब यह कि फ्रांस में माला खत्म नहीं, बल्कि घसीटते हुए अभी भी जिंदा है।

ये सारे बवाल खत्म हो जाएं शर्तें राहुल गांधी राजनीति छोड़ दें। राहुल की आवाज मौन हो जाए। मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी या शरद पवार या एकसर्वाईजेड दूसरा कोई नेता अद्वितीय ब्लॉक का चेयरमेन बना तो राहुल गांधी का बोलना बंद होगा। मगर हां यह संभव है कि ममता बनर्जी की अश्वस्ता में अखिलेश, लालू यादव, शरद पवार सब मिल कर कोलकाता या मुंबई में अपने मध्य पर गौतम अडानी का अमिन्टन समारोह करें। विषय नरेंद्र मोदी से अपील करें कि भारत की वैश्विक ख्याति में योगदान के लिए गौतम अडानी को उहाँसे भारत रख देना चाहिए।

फिल्मी दुनिया/सेहत

पुष्पा 2 ने किया 1400 करोड़ का आंकड़ा पार, अब ओटीटी पर हस दिन रिलीज होगी अल्लू अर्जुन की फिल्म

पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ढेर लगा दिया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12 दिन पूरे कर लिए हैं और फिल्म ने इन 12 दिनों में 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। इस बीच पुष्पा 2 के ओटीटी पर रिलीज होने की डेट की खबरें आ गई हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि फिल्म पुष्पा 2 आगामी जनवरी 2025 में रिलीज होने जा रही है। फिल्म पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 12 वें दिन कितनी कमाई की और फिल्म ओटीटी पर कब आएगी जानते हैं।

राजामौली की आरआरआर बिहाइंड एंड वियाकू वाक्यांकेंद्री का ट्रेलर उत्तीर्ण

एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित 2022 की महाकाव्य पीरियड एक्शन फिल्म आरआरआर, दुनिया भर में सनसनीखी का बिपाठ ड्रेस दिखाती है।

गई, जिसने दिग्गज फ़िल्म निर्माता जेम्स कैमरून और स्टीवन स्पीलबर्ग सहित वफादार प्रशंसकों और प्राकृष्टिक किया। एक्शन तमाशा के पीछे की टीम ने अब फ़िल्म के निर्माण के बारे में एक डॉक्यूमेंटी जारी करने

की है, जिसका शीर्षक आरआरआर बिहाइंड एंड बियॉन्ड है। डॉक्यूमेंट्री का ड्रेलर सामने आ गया है, जिसमें महात्मा समय टीम के समर्पण, दृढ़ विश्वास और जुनून की झलकियाँ दी गई हैं। ड्रेलर में फिल्म के प्रमुख सितारे जूनियर और राम चरण फिल्म और इसके निर्देशक एसएस राजामौली के बारे में अज्ञात कहानियाँ और रोचक तथ्य हैं। डॉक्यूमेंट्री में आलिया भट्ट और अजय देवगन सहित फिल्म की पूरी कास्ट के साथ-साथ डीओपी सेंथिल कुमारीकर प्रसाद और प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरिल सहित फिल्म की क्रू भी शामिल हैं। ड्रेलर धमाकेदार तरीके से होता है, जिसमें अकादमी पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू की मेकिंग दिखाई जाती है, जिसे एमएम कीरावर्णन किया है और चंद्रबोश ने लिखा है। आरआरआर बिहाइंड एंड बियॉन्ड 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली प्रशंसकों को आरआरआर के जादू का अनुभव करने का मौका मिलेगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यह फिल्म प्रशंसकों को महाकाव्य फिल्म के निर्माण में एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने का बादा करती है, जिसमें इस उत्कृष्ट कृति में लगी कड़ी मेहनत, समर्पण और जुनून को दिखाया गया है। डीवीडी दानन्द्या द्वारा डीवीडी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले निर्मिता भारत में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। आरआरआर बिहाइंड एंड बियॉन्ड के साथ प्रशंसकों को फिल्म और रोमांच को फिर से जीने का मौका मिलेगा, और इस महाकाव्य फिल्म के निर्माण का अनुभव पहले कभी नहीं हुआ।

हिट द थर्ड केस के सेट से नानी की तस्वीर वायरल, फिल्म के लिए अभिनेता ने अपनाया यह खास लुक

अक्षय कुमार की स्काई फोर्स से लीक हुआ सारा अली खान और वीर पहाड़िया का वीडियो, डांस करते दिखे

अक्षय कुमार की स्काई फोर्स देशभक्ति पर आधारित फिल्म 4 जनवरी, 2025 को रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज से पहले गढ़वाली गाने बीटीएस वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया है, जिसमें वीर और आरा अली खान डांस मूव्स करते नजर आ रहे हैं। निर्देशक संदीप केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर द्वारा अपनी पहली निर्देशित देशभक्ति फिल्म स्काई फोर्स को लेकर प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं। फिल्म स्काईफोर्स के सेट से गढ़वाली गाने पर सारा अली खान और वीर पहाड़िया के डांस का एक वायरल वीडियो ऑनलाइन भाग हुआ है। इस वायरल वीडियो में आरा अली खान और वीर पहाड़िया को गढ़वाली गाने पर चरकते और डांस करते देखा जा सकता है।



A photograph of a woman in a bright pink, strapless, knee-length dress. She is standing with her hands clasped gently over her pregnant belly. She is wearing a necklace with a large green pendant and several rings on her fingers. The background is a soft-focus indoor setting.

